

केमिकल्स एंड फाइबर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ईटीसी

बनाम

भारत संघ

11 फ़रवरी 1991

[एस रंगनाथन, एन.एम. कासलीवाल और एस.सी. अग्रवाल, जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियम, 1971-धारा 37 और धारा 75-नियम 3, 4, 6 और 7 -डाइ-मिथाइल-टेरेफ्थेलेट -का आयात-क्या निर्धारिती भुगतान किए गए सीमा शुल्क की पूरी 'वापसी' का हकदार है।

अपीलकर्ता पॉलिएस्टर फाइबर यार्न के निर्माता हैं। उन्होंने उक्त धागे की आपूर्ति के लिए इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, सिंगापुर से एक अनुबंध प्राप्त किया और उक्त कंपनी ने अपीलकर्ताओं को पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर यार्न के निर्माण के लिए आवश्यक डाइ-मिथाइल-टेरेफ्थेलेट (डीएमटी) की मुफ्त आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी। डीएमटी को पॉलिएस्टर फाइबर में परिवर्तित करने, स्वदेशी रूप से विस्कोस के साथ मिश्रित करने और श्रीलंका में आईसीआई के एक ग्राहक को भेजने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता निर्धारितियों ने 392 टन डीएमटी और 178 टन विस्कोस स्थिर

फाइबर के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट प्राप्त किए। अपीलकर्ताओं ने सीमा शुल्क बांड के तहत आयातित डीएमटी को पॉलिएस्टर फाइबर में बदलने की अनुमति भी प्राप्त की। अपीलकर्ताओं ने डीएमटी का आयात किया और उसके संबंध में सीमा शुल्क का भुगतान किया। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 केंद्र सरकार को किसी वर्ग या विवरण के किसी भी आयातित सामग्री पर अधिनियम के तहत लगाए गए सीमा शुल्क की कटौती की अनुमति देने का अधिकार देती है। उप-धारा (2) के तहत नियमों के अनुसार और उनके अधीन ऐसे सामानों का निर्माण। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 37 में एक समान प्रावधान है जो ऐसे निर्माण के संबंध में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी को सक्षम बनाता है।

केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियम 1971 बनाए, जिससे सीमा शुल्क के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में ड्रॉबैक का लाभ उठाया जा सके। अधिसूचना की अनुसूची II में उन वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनका निर्यात एक निर्धारिती को ड्रॉबैक सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार देता है। अधिसूचना की अनुसूची II में उन वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनका निर्यात एक निर्धारिती को ड्रॉबैक सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार देता है। इसलिए निर्धारिती ने 23-3-1977 को वित्त मंत्रालय को एक आवेदन देकर अनुरोध

किया कि चूंकि उसने डीएमटी पर सीमा शुल्क का भुगतान किया था, इसलिए वह इसकी वापसी का हकदार था, विशेष रूप से जब उसने सीमा शुल्क बांड के तहत पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए अनुरोध किया था। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मना कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को केंद्र सरकार ने 12.3.1978 को खारिज कर दिया था, हालांकि पॉलिएस्टर स्टेपल फैब्रिक के निर्माता एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किए गए एक प्रतिनिधित्व पर धारा 25 के तहत 2-8-76 को एक अधिसूचना जारी की गई थी सीमा शुल्क अधिनियम डीएमटी को सीमा शुल्क से छूट देते हुए। इसके बाद अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए ये अपीलें।

अपीलों को खारिज करते हुए, लेकिन केंद्र सरकार से अपीलकर्ताओं के मामले पर न्यायसंगत आधार पर विचार करने की सिफारिश करते हुए कि क्या उसे राहत दी जा सकती है।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

हालांकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 37 सरकार को अधिकार देती है। व्यक्तिगत निर्माताओं द्वारा भुगतान किए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के पुनर्भुगतान के लिए भी प्रावधान करें, बनाए गए

नियम (विशेष रूप से नियम 3) केवल किसी विशेष वर्ग या माल के विवरण की सामग्री पर भुगतान की गई शुल्क की औसत राशि की वापसी के लिए प्रदान करते हैं। नियम 7 के तहत निर्धारित सीमा को छोड़कर, आमतौर पर निर्माताओं द्वारा उस वर्ग या विवरण के निर्यात माल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। [300 ए-बी']

नियमों में सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर अंकगणितीय राशि की वापसी की परिकल्पना नहीं की गई है जिसका भुगतान वास्तव में किसी व्यक्तिगत आयातक-सह-निर्माता द्वारा किया गया हो। यदि यह वैधानिक इरादा होता, तो यह प्रदान करना आसान होता कि उन सभी मामलों में जहां आयातित कच्चे माल का पूरी तरह से निर्यात किए जाने वाले सामान के निर्माताओं में उपयोग किया जाता है, निर्धारित आयात या विनिर्माण के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क को वापस लेने का हकदार होगा। [300 सी]

इसमें कोई विवाद नहीं है कि, इस मामले में, निर्यात किया गया सामान आइटम 25 के अंतर्गत आता है। यह तर्क देने की कोशिश की गई कि सामान उप-आइटम 2501 के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है। उप-आइटम 2501 एक अवशिष्ट श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो उन वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होगा जो स्पष्ट रूप से उप-आइटम 2502 के अंतर्गत आते हैं। अधिसूचना यार्न की संरचना और इसकी सामग्री

की प्रकृति के आधार पर इस मद के तहत अलग-अलग मात्रा में कमी निर्धारित करती है। अधिसूचना यार्न की संरचना और इसकी सामग्री की प्रकृति के आधार पर इस मद के तहत अलग-अलग मात्रा में कमी निर्धारित करती है।

यह उन वस्तुओं के विरुद्ध उपलब्ध ड्राबैक के माध्यम से राहत के रूप में 43.15 रुपये प्रति किलोग्राम की राशि निर्दिष्ट करता है, जिनसे हमारा संबंध है, जो आइटम 2502 के खंड (बी) के अंतर्गत आते हैं। [300 एच-301 बी]

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही था कि डीएमटी के संबंध में देय सीमा शुल्क के पहलू पर विचार करने के बाद प्रश्न में माल के संबंध में वापसी की दर तय की गई थी और यह एक सचेत निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए प्रदान किया जाए क्योंकि डीएमटी देश में ही उपलब्ध था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां निर्धारण नियम 3 की शर्तों के विपरीत है, और उसके मामले में दर के निर्धारण के लिए निर्धारिती के आवेदन को नियम 6 के तहत एक आवेदन के रूप में लिया जाना चाहिए। [303 बी]

नियम 6 इस कारण से भी लागू नहीं है कि निर्माता के माल के निर्यात से पहले नियम 6 के तहत आवेदन किया जाना चाहिए जो यहाँ मामला नहीं लगता है। [303 सी]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 692/1981 और
693/1981

दिल्ली उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 883/1978 और
1079 ऑफ 1979 में के निर्णय और आदेश दिनांक 19.5.1980 से।

आर.के. हब्बू, आर.बी. हाथीखानवाला और बी.आर. अपीलकर्ताओं के
लिए अग्रवाल।

प्रतिवादी की ओर से सोली जे. सोराबजी, अटॉर्नी जनरल (एनपी),
कपिल सिब्बल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री इंदु मल्होत्रा, पी.
परमेश्वरन और सी. वी. सुब्बा राव।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथन जे. द्वारा सुनाया गया ।

इन दोनों अपीलों में एक सामान्य प्रश्न शामिल है और इन्हें एक
सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या
अपीलकर्ता कंपनियां (बाद में 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) सीमा शुल्क
की पूरी "वापस लेने" की हकदार हैं, जो उन्होंने डाइ-मिथाइल-टेरेफ्थेलेट
(जिसे जल्द ही 'डीएमटी' कहा जाता है) के आयात पर भुगतान किया था।)
पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर यार्न के निर्माण के लिए। मूल्यांकनकर्ताओं ने
डीएमटी को ठाणे में अपने कारखाने में पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर में
परिवर्तित किया और फिर इसे राजस्थान के भीलवाड़ा भेजा, जहां राजस्थान

स्पिनिंग और वीविंग मिल्स ने मिश्रित यार्न की कुछ किस्मों को निकालने के लिए इसे स्वदेशी विस्कोस स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित किया। यह सामान्य बात है कि इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद को निर्धारितियों द्वारा इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात किया गया था। लिमिटेड सिंगापुर, जिसने निर्धारितियों को निःशुल्क डीएमटी की आपूर्ति की थी। प्रश्न का उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रा बैक नियम, 1971 के साथ पढ़ा जाता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश देने का अधिकार देती है भारत में निर्मित और भारत के बाहर किसी भी स्थान पर निर्यात किए जाने वाले किसी भी वर्ग या विवरण के सामान की वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए उक्त धारा की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और उनके अधीन, ऐसे सामानों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली किसी भी वर्ग या विवरण की आयातित सामग्री पर अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क। उप-धारा 2, जो नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, अधिनियमित करती है कि ऐसे नियम, अन्य बातों के अलावा, प्रदान कर सकते हैं:

"(ए) माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली आयातित सामग्रियों पर वास्तव में भुगतान की गई शुल्क की राशि के बराबर डॉ बँक के भुगतान के लिए या जैसा कि नियमों में उस वर्ग की सामग्रियों पर भुगतान की गई शुल्क की औसत राशि के रूप में निर्दिष्ट है या आमतौर पर निर्माताओं द्वारा या किसी विशेष निर्माता द्वारा उस वर्ग या विवरण के निर्यात माल के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला विवरण;"

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 37 में एक समान प्रावधान है जो ऐसे निर्माण के संबंध में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी को सक्षम बनाता है।

केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क डॉबँक नियम, 1971 (इसके बाद इसे 'के रूप में संदर्भित किया गया है) तैयार किया (नियम'), इन दो कानूनों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। ये उपरोक्त दो प्रावधानों के तहत समग्र नियम हैं और सीमा शुल्क के संबंध में डॉबँक का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में भी। इन नियमों के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को यहां उद्धृत किया

जा सकता है। नियम 3, जहां तक यह हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

नियम 3: कमी: (1)_: _ के प्रावधानों के अधीन

(ए) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और उसके तहत बनाए गए नियम।

(बी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियम, और

(सी) ये नियम,

(ए) अनुसूची II में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात पर ऐसी राशि पर, या ऐसी दरों पर, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है, वापसी की अनुमति दी जा सकती है।

XXX XXX XXX

(2) इस नियम के तहत वापसी की राशि या दर निर्धारित करने में, केंद्र सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी:

(ए) प्रत्येक वर्ग की औसत मात्रा या मूल्य या सामग्रियों का विवरण जिससे भारत में किसी विशेष वर्ग के सामान का सामान्य रूप से उत्पादन या निर्माण किया जाता है।

(बी) किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं के भारत में उत्पादन या निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों की औसत मात्रा या मूल्य।

(सी) माल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सेमी, घटकों और मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर भुगतान की गई शुल्क की औसत राशि।

(डी) निर्माण और उत्प्रेरक एजेंटों की प्रक्रिया में बर्बाद हुई सामग्रियों पर भुगतान किए गए शुल्क की औसत राशि:

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी अपशिष्ट या उत्प्रेरक एजेंट का उपयोग निर्माण की किसी प्रक्रिया में किया जाता है या बेचा जाता है, तो इस प्रकार उपयोग किए गए या बेचे गए अपशिष्ट या उत्प्रेरक एजेंट पर शुल्क की औसत राशि भी काट ली जाएगी।

(ई) निर्यातित वस्तुओं को रखने या पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर भुगतान किए गए शुल्क की औसत राशि।

(एफ) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की औसत राशि: और

(छ) कोई अन्य जानकारी जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक या उपयोगी मान सकती है।

नियम 4. दरों में संशोधन: केंद्र सरकार नियम 3 के तहत निर्धारित राशि या दरों को संशोधित कर सकती है।

XXX XXX XXX

6. ऐसे मामले जहां ड्रॉबैक की राशि या दर निर्धारित नहीं की गई है

(1)(ए) जहां किसी भी सामान के संबंध में वापसी की कोई राशि या दर निर्धारित नहीं की गई है; ऐसे माल का कोई भी निर्माता या निर्यातक, ऐसे माल का निर्यात करने से पहले, वापसी की राशि या दर के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है, जिसमें उत्पादन में सामग्री या घटकों का उपयोग किए जाने वाले अनुपात सहित सभी प्रासंगिक तथ्य शामिल होंगे। या माल का निर्माण और ऐसी सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किया गया शुल्क।

(बी) खंड (ए) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर केंद्र सरकार ऐसी जांच करने या करवाने के बाद जो वह उचित समझे, ऐसे सामानों के संबंध में वापसी की राशि या दर निर्धारित करेगी।

7. ऐसे मामले जहां निर्धारित वापसी की राशि या दर कम है-(1) जहां किसी भी ऐसे सामान के संबंध में, निर्माता या निर्यातक को पता

चलता है कि वापसी की राशि या दर नियम 3 के तहत निर्धारित की गई है या, जैसा भी मामला हो, संशोधित किया गया है सामान के उस वर्ग के लिए नियम 4, उक्त सामान के उत्पादन या निर्माण में प्रयुक्त सामग्री या घटकों पर भुगतान किए गए शुल्क के तीन चौथाई से कम है, वह उचित राशि या ड्रॉबैक की दर निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है माल के उत्पादन या निर्माण में सामग्री या घटकों का उपयोग किस अनुपात में किया जाता है और ऐसी सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किए गए शुल्क सहित सभी प्रासंगिक तथ्य।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, ऐसी जांच करने या करवाने के बाद, जो वह उचित समझे, ऐसे निर्यातक को ऐसी राशि या ऐसी दर पर वापसी का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है यदि नियम 3 के तहत निर्धारित राशि या दर या, जैसा भी मामला हो, नियम 4 के तहत संशोधित, वास्तव में इस उप-नियम के तहत निर्धारित ऐसी राशि या दर के तीन चौथाई से कम है, तो उपयुक्त माना जा सकता है।

अधिसूचना की अनुसूची II जिसके द्वारा नियमों को प्रख्यापित किया गया था, सूचीबद्ध है

वे वस्तुएँ जिनका निर्यात करदाता को ड्रॉबैक सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार देता है। सूची का आइटम 25 इस प्रकार है:

"सिंथेटिक और पुनर्जीवित फाइबर, कपड़ा धागा, धागा, सुतली, डोरियाँ और रस्सियाँ।"

यह सामान्य आधार है कि निर्धारितियों द्वारा निर्यात किया गया माल उपरोक्त मद 25 के अंतर्गत आता है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि निर्धारितियों द्वारा आयातित डीएमटी का उपयोग उपरोक्त वस्तु के निर्माण के लिए किया गया था और डीएमटी के आयात पर, निर्धारितियों ने सीमा शुल्क का भुगतान किया है।

विभिन्न वस्तुओं के संबंध में उपलब्ध ड्राबैक की दरों को केंद्र सरकार द्वारा उचित समय पर अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना में क्रम संख्या 25 के समक्ष प्रतिअदायगी की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:

सीरीयल नम्बर	सब एसआई. संख्या	माल का विवरण	ड्राबैक की दर
25.	2501	सिंथेटिक और पुनर्जीवित टेड फाइबर और कपड़ा धागा/धागा, सुतली, डोरियाँ और रस्सियाँ	व्यक्तिगत निर्माता निर्यातक के

		धागा, धागा, सुतली, डोरियाँ और रस्सियाँ जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।	आवेदन पर ब्रांड दर तय की जाएगी।
	2502	{ए) 21 बीडब्ल्यूएस काउंट से ऊपर या 14 एन.एफ. से ऊपर का सूत। गिनती, पूरी तरह से विस्कोस रेयान फाइबर या एसीटेट फाइबर या पॉलीस्टर फाइबर, पॉलियामाइड फाइबर या ऐक्रेलिक फाइबर या ऊन से, या दो के संयोजन से और ऊपर उल्लिखित फाइबर में से दो से अधिक नहीं, या इनमें से किसी	

		<p>एक के संयोजन से। कपास या रेशम के साथ उपरोक्त उल्लिखित रेशे (लेकिन प्राप्त रेशों से काते गए सूत को छोड़कर)।</p> <p>फाइबर अपशिष्ट, सूत अपशिष्ट या कपड़े अपशिष्ट, गर्नेटिंग द्वारा या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा:</p>	
(ए) सेल्युलॉसिक फाइबर सामग्री:			1.80 रुपये (एक रुपये अस्सी पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(बी) इंटरनेट आधारित सामग्री:			43.15 रुपये (तयालीस रुपये पन्द्रह पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(सी) एक्रिलिक फाइबर सामग्री:			37 रु. 75 (सैंतीस रुपये और पचहत्तर पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(डी) पॉलियामाइड फाइबर सामग्री:			16.40 रुपये (सोलह रुपये चालीस

	पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(ई) ऊन सामग्री:	
(i) रु. 18.95 के सबसे खराब धागे में (अट्ठारह रुपये और पैसे बुनाई की गुणवत्ता से बना ऊनी शीर्ष)	18.95 रुपये (अट्ठारह रुपये पंचानवे पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(ii) बुनाई की गुणवत्ता के सबसे खराब धागे में, जो ऊन के शीर्ष से नहीं बना है।	13.55 रुपये (तेरह रुपये पचपन पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(iii) ऊनी टॉप से बने वेस्टेड होजरी यार्न और वेस्टेड हैंड निटिंग यार्न में	16.65 रुपये (सोलह रुपये पैंसठ पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(iv) वेस्टेड होजरी यार्न और वेस्टेड हैंड निटिंग यार्न में जो ऊनी ऊपरी भाग से नहीं बना हो	रु. 11.25 (ग्यारह रुपये और पच्चीस पैसे मात्र) प्रति किलोग्राम।
(v) यदि सूत रंगा हुआ है तो सामग्री को अलविदा कहें	रु.0.85 (पचासी पैसे मात्र) प्रति किग्रा.

XXX XXX XXX

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निर्धारित पॉलिएस्टर फाइबर सामग्री के प्रति किलोग्राम 43.15 रुपये की छूट के हकदार हैं।

उनके द्वारा निर्यात किया गया सूत। हमें सूचित किया गया है कि यह पॉलिएस्टर फाइबर सामग्री वाले यार्न के निर्माण के संबंध में देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर है। वर्तमान में बताए जाने वाले कारणों के लिए, निर्धारिती को निर्माण के लिए कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ता था और इसलिए निश्चित रूप से निर्धारिती को इस हद तक छूट मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। निर्धारिती द्वारा उठाया गया मुद्दा यह है कि, डीएमटी पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद, वह डीएमटी पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क के संबंध में वापसी का हकदार था। चूंकि इसे केंद्र सरकार की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारितियों ने 23.3.1977 को वित्त मंत्रालय को एक आवेदन देकर अनुरोध किया कि संपूर्ण सीमा शुल्क की वापसी को मंजूरी दी जाए। हालाँकि, इस अनुरोध को केंद्र सरकार ने दिनांक 12.3.1978 के एक संचार द्वारा अस्वीकार कर दिया था। यह संचार निम्नलिखित शब्दों में था:

"सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियम 1971 के नियम 3 के तहत, पॉलिएस्टर विस्कोस मिश्रित यार्न पर ड्रॉबैक की सभी उद्योग दरें ड्रॉबैक अनुसूची के क्रम संख्या 2502 के तहत निर्धारित और घोषित

की गई हैं। उक्त दरें निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए भौतिक समय पर निर्धारित की गई हैं:

(ए) विस्कोस फाइबर के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की शुल्क घटना, साथ ही विस्कोस फाइबर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और

(बी) पॉलिएस्टर यार्न के संबंध में पॉलिएस्टर फाइबर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क।

हालाँकि, पॉलिएस्टर यार्न के निर्माण के लिए किसी कच्चे माल पर शुल्क को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि यह (डीएमटी) स्वदेशी रूप से उपलब्ध है और इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। 18.8.1977 से प्रभावी निर्धारित दरों के लिए, हालाँकि आयातित और स्वदेशी सामग्री के भारत औसत के आधार पर डीएमटी पर शुल्क की घटना को भी ध्यान में रखा गया है।"

केंद्र सरकार के इस फैसले से असंतुष्ट करदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जो थी 19.5.80 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गयी है।

इस स्तर पर, कुछ तथ्यों को रेखांकित करना आवश्यक हो सकता है जो उस पृष्ठभूमि की सराहना करने के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं जिसमें करदाता के वकील ने सीमा शुल्क की कमी के लिए अपीलकर्ता के न्यायसंगत, यदि कानूनी भी नहीं, दावों का दृढ़ता से आग्रह किया था। वकील का दावा है कि मूल्यांकनकर्ता पॉलिएस्टर फाइबर यार्न का निर्माण करने वाले भारत में उद्यमियों का लगभग पहला समूह थे। वे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, सिंगापुर से अनुबंध प्राप्त करने के लिए काफी भाग्यशाली थे। दिनांक 02.04.75 के एक पत्र द्वारा यह कंपनी 67 प्रतिशत पॉलिएस्टर और 33 प्रतिशत विस्कोस फाइबर से युक्त मिश्रित यार्न के निर्माण के लिए आवश्यक डीएमटी की निःशुल्क आपूर्ति करने पर सहमत हुई। डीएमटी को पॉलिएस्टर फाइबर में परिवर्तित किया जाना था, स्वदेशी रूप से विस्कोस के साथ मिश्रित किया जाना था और श्रीलंका में आईसीआई के एक ग्राहक को भेजा जाना था। इसके बाद, 02.06.75 को, निर्धारितियों ने 392 टन डीएमटी और 178 टन विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट प्राप्त किया। अंततः, हालांकि, विस्कोस स्टेपल फाइबर स्वदेशी रूप से प्राप्त किया गया था और इस सीमा तक आयात परमिट का उपयोग निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था। इस परमिट को प्राप्त करने के समय, निर्धारितियों ने सीमा शुल्क बांड के तहत आयातित डीएमटी को पॉलिएस्टर फाइबर में परिवर्तित करने की अनुमति

भी प्राप्त की। सीमा शुल्क निकासी परमिट से जुड़ी शर्त निम्नलिखित शर्तों में थी:

"कंपनी सीमा शुल्क बांड के तहत आयातित डीएमटी को पॉलिएस्टर फाइबर में परिवर्तित करेगी। इसके बाद कंपनी निर्मित पॉलिएस्टर फाइबर और आयातित विस्कोस स्टेपल फाइबर को बॉन्ड के तहत राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा के बंधुआ गोदाम में ले जाएगी। इसके बाद मेसर्स राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स फर्म की ओर से बॉन्ड पॉलिएस्टर विस्कोस रतालू का निर्माण करेगी। इसके बाद पॉलिएस्टर विस्कोस फाइबर रतालू को फर्म द्वारा उन विदेशी खरीदारों को निर्यात किया जाएगा जिन्होंने सीसीपी आधार पर डीएमटी और विस्कोस स्टेपल फाइबर की आपूर्ति की है या उनके नामांकित व्यक्तियों को.... "

यदि ये शर्तें पूरी हो जातीं तो करदाताओं को कोई समस्या नहीं होती। पॉलिएस्टर फाइबर का निर्माण सीमा शुल्क बांड के तहत किया गया होगा और इससे करदाताओं को सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्ति मिल जाती। इसी प्रकार, राजस्थान कताई और बुनाई मिलों में मिश्रित रतालू का उत्पादन केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर्यवेक्षण के तहत होता और निर्माण पर

कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं होता। दुर्भाग्य से, हालांकि, सीमा शुल्क अधिकारी उन कारणों से सीमा शुल्क बांड के तहत डीएमटी को पॉलिएस्टर फाइबर में बदलने की अनुमति देने की स्थिति में नहीं थे जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हैं और जिन्हें इन कार्यवाहियों में चुनौती नहीं दी जा रही है। सीमा शुल्क बांड के तहत पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए निर्धारिती के अनुरोध को सीमा शुल्क अधिकारियों ने 02.04.1976 को अस्वीकार कर दिया था। शायद इस कठिनाई का अनुमान लगाते हुए, बॉम्बे में पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर निर्माताओं के संघ ने 26.03.1976 को केंद्र सरकार को एक आवेदन दिया और पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिए आवश्यक डीएमटी पर सीमा शुल्क से छूट की प्रार्थना की। यह पत्र इंगित करता है:

"इस एसोसिएशन के सदस्य पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का निर्माण करते हैं। हमारे एक सदस्य को डीएमटी के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसकी एक फोटोस्टेट प्रति हम इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। इस डीएमटी का उपयोग पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए किया जाना है और पॉलिएस्टर फाइबर को फिर निर्यात ऑर्डर के खिलाफ आपूर्ति के लिए यार्न में परिवर्तित किया जाएगा। हमारे सदस्य इस तरीके से बड़े निर्यात कारोबार की संभावना तलाशना चाहते हैं।

डीएमटी और ग्लाइकोल दोनों की स्वदेशी आपूर्ति घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और निर्यात व्यवसाय केवल दो सामग्रियों के आयात से ही किया जा सकता है। हमारे सदस्य को जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस का उपयोग करके निर्यात आदेशों को पूरा करने से कुछ समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि लाइसेंस में सीमा शुल्क बांड के तहत निर्माण निर्धारित होता है।

आप बांड के तहत विनिर्माण में कठिनाई की सराहना करेंगे जब निर्यात के लिए फाइबर कारखाने के कुल निर्माण का केवल एक हिस्सा बनता है। यदि डीएमटी और ग्लाइकोल को सीमा शुल्क अधिसूचना जीएसआर 183 की अनुसूची में शामिल किया जा सकता है, तो बॉन्ड के तहत विनिर्माण में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां लागू नहीं होंगी। अग्रिम लाइसेंस के तहत प्राप्त कच्चे माल से बने रतालू के निर्यात से प्रसंस्करण के दौरान जोड़े गए मूल्य के कारण काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।"

करदाताओं में से एक ने भी इसी तरह का अनुरोध किया और अंततः, 2 अगस्त, 1976 को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत

डीएमटी को सीमा शुल्क से छूट देने की अधिसूचना जारी की गई। भारत सरकार ने भी 09.09.76 को उपस्थित अपीलकर्ताओं में से एक को उक्त अधिसूचना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा और कहा कि इस अधिसूचना को जारी करने के साथ। ऐसा प्रतीत होगा कि करदाता की समस्या हल हो गई है। हालाँकि, यह सही नहीं था। अधिसूचना में डीएमटी के भविष्य के आयात को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, लेकिन जिन करदाताओं ने पहले डीएमटी का आयात किया था, उन्हें उस पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद इसे खाली करना होगा। इसलिए उनके द्वारा पहले से भुगतान किए गए सीमा शुल्क की वापसी के लिए उनका अनुरोध, जिसके इनकार के कारण वर्तमान मुकदमा चल रहा है।

अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को माल को छूट देने में सक्षम बनाते हैं। धारा 25 के तहत आयात के समय सीमा शुल्क लगाने से या ऐसा न करने पर, धारा 75 में निर्धारित शर्तों के पूरा होने की स्थिति में भुगतान किए गए सीमा शुल्क में कमी की अनुमति देने के लिए। वर्तमान मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत छूट वास्तव में अधिसूचित की गई थी लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल अगस्त, 1976 में हुआ। इस समय तक, निर्धारिती पहले ही डीएमटी आयात कर चुके थे। श्रीलंका में निर्मित फाइबर के निर्यात के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के

कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। वकील का कहना है कि, शुरू से ही, करदाता इस आधार पर आगे बढ़े थे कि वे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त करेंगे, क्योंकि आईसीआई से कुछ रूपांतरण शुल्क प्राप्त करने के अलावा, लेनदेन पर लाभ का उनका अपना मार्जिन पर्याप्त नहीं था। इसीलिए सीमा शुल्क निकासी परमिट प्राप्त करते समय भी उन्होंने सीमा शुल्क बांड के तहत डीएमटी को पॉलिएस्टर में बदलने की अनुमति मांगी थी। यदि ऐसा किया गया होता, तो सीमा शुल्क का भुगतान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। दुर्भाग्य से, क्योंकि विभाग के पास इस तरह के ऑपरेशन की निगरानी के लिए सुविधाओं की कमी थी, इसलिए करदाताओं का प्रयास केवल आंशिक रूप से ही था इसमें सफलता मिली कि वे केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर्यवेक्षण के तहत मिश्रित फाइबर का उत्पादन करने में सक्षम थे।

डीएमटी से पॉलिएस्टर फाइबर में रूपांतरण का प्रारंभिक चरण सीमा शुल्क बांड के तहत नहीं किया जा सका। यह बताया गया है कि भारत सरकार ने करदाताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर ही डीएमटी को सीमा शुल्क से छूट दी थी और यह आग्रह किया गया है कि करदाताओं को सीमा शुल्क की छूट देने से इनकार करना पूरी तरह से अनुचित है।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 27 के साथ पढ़ा जाता है, का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह प्रदान करना है कि ऐसे मामलों में जहां कुछ वस्तुओं को निर्यात किए जाने वाले सामानों के निर्माण में पूर्ण उपयोग के लिए आयात किया जाता है, आयातक को सक्षम होना चाहिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में राहत प्राप्त करें। वर्तमान मामले में कोई विवाद नहीं है कि डी.एम.टी. निर्धारिती द्वारा आयातित का उपयोग पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिए किया गया था और अंतिम उत्पाद पूरी तरह से श्रीलंका को निर्यात किया गया था। हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों के तहत की गई अधिसूचना, केवल पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण में शामिल उत्पाद शुल्क के संबंध में कमी का प्रावधान करती है, लेकिन वास्तव में आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क का नहीं। विद्वान वकील श्री हब्बू का तर्क है कि यह अधिसूचना, वास्तव में, नियम 3 में निहित प्रावधान के विपरीत है, जो सरकार को अन्य बातों के अलावा, कमी की राशि या दर निर्धारित करने के लिए बाध्य करती है, निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली आयातित या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क की राशि। उनका कहना है कि, जहां तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरें डीएमटी पर आयात शुल्क के तत्व को ध्यान में नहीं रखती हैं, निर्धारण नियम के अनुसार नहीं है। उनके अनुसार, इसलिए, यह मामला नियम 6 के अंतर्गत आता है जो एक निर्धारिती को केंद्र

सरकार को यह निर्धारित करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है कमी जहां कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार ने निर्धारिती के आवेदन को नियम 7 के तहत आने वाले आवेदन को खारिज करने में गलती की है और इसलिए यह कानून और इक्विटी दोनों में स्वीकार्य नहीं है।

निर्धारितियों के विद्वान वकील को कुछ विस्तार से सुनने के बाद, हमारी राय है कि निर्धारिती की दलीलों को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही था। हमारा मानना है कि करदाता के तर्क एक बुनियादी गलतफ़हमी पर आधारित हैं कि, अधिनियमों और नियमों के तहत, यदि धारा 75 के नियम और शर्तें पूरी होती हैं, तो निर्माता स्वचालित रूप से उसके द्वारा भुगतान किए गए संपूर्ण सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की कटौती का हकदार है। यद्यपि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 37 सरकार को व्यक्तिगत निर्माताओं द्वारा भुगतान किए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के पुनर्भुगतान के लिए भी अधिकार प्रदान करती है, लेकिन बनाए गए नियम (विशेष रूप से नियम 3) केवल प्रदान करते हैं आम तौर पर निर्माताओं द्वारा उस वर्ग या विवरण के निर्यात माल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी विशेष वर्ग या विवरण के माल की "सामग्री पर भुगतान की गई शुल्क की औसत राशि" की वापसी के लिए, नियम 7

के तहत निर्धारित सीमा को छोड़कर (वर्तमान में ध्यान देने योग्य)। नियम अंकगणितीय रूप से सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर राशि की वापसी की परिकल्पना नहीं करते हैं जो वास्तव में एक व्यक्तिगत आयातक-सह-निर्माता द्वारा भुगतान किया गया हो सकता है। यदि यह वैधानिक इरादा होता, तो यह प्रदान करना आसान होता कि उन सभी मामलों में जहां आयातित कच्चे माल का पूरी तरह से निर्यात किए जाने वाले सामानों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, निर्धारित आयात या विनिर्माण के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क में कटौती का हकदार होगा। दूसरी ओर, धारा 75(2) के तहत किसी विशेष व्यापार में प्रचलित सभी परिस्थितियों पर विचार करके ड्रॉबैक की राशि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। और आयातित और निर्मित वस्तुओं के विभिन्न वर्गों में से प्रत्येक के संबंध में प्रासंगिक तथ्य स्थिति। नियम 3 में परिकल्पित निर्धारण की एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करने की आवश्यकता है। किसी विशेष निर्मित वस्तु के विभिन्न निर्माता हो सकते हैं। उनमें से कुछ स्वदेशी सामग्री का उपयोग कर रहे होंगे और कुछ कच्चे माल का आयात कर रहे होंगे। इसी प्रकार विनिर्माण की प्रक्रिया में भी निर्माता और विनिर्माता के बीच अंतर हो सकता है। इसीलिए ड्रॉबैक नियम "औसत" राशि को ध्यान में रखने के बाद ड्रॉबैक के निर्धारण का प्रावधान करते हैं अनुसूची II में सूचीबद्ध प्रत्येक प्रकार के सामान के संबंध में नियम 3 में निर्दिष्ट विभिन्न वस्तुओं में से प्रत्येक का सम्मान। जारी

अधिसूचना विभिन्न श्रेणियों के सामानों के संबंध में आयातकों-सह-निर्माताओं को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों के संबंध में उपलब्ध समग्र कमी को भी निर्धारित करती है। दूसरे शब्दों में, ड्राबैक की राशि का उद्देश्य उन कर्तव्यों की राशि नहीं है जो व्यक्तिगत निर्माताओं द्वारा भुगतान किया गया हो; इसका निर्धारण अनुसूची II में निर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में देश में प्रचलित समग्र स्थिति पर विचार करके किया जाना है। हमारा मानना है कि यदि इस मूल सिद्धांत को समझ लिया जाये तो सरकार का निर्णय बन जायेगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि, इस मामले में, निर्यात किया गया सामान आइटम 25 के अंतर्गत आता है। विद्वान वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि यहां सामान उप-आइटम 2501 के अंतर्गत आता है लेकिन यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है। उप-आइटम 250 एक अवशिष्ट श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो यहां उन वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होगा जो स्पष्ट रूप से उप-आइटम 2502 के अंतर्गत आते हैं। अधिसूचना यार्न की संरचना और इसकी सामग्री की प्रकृति के आधार पर इस मद के तहत अलग-अलग मात्रा में कमी निर्धारित करती है। यह उन वस्तुओं के विरुद्ध उपलब्ध ड्राबैक के माध्यम से राहत के रूप में 43.15 रुपये प्रति किलोग्राम की राशि निर्दिष्ट करता है, जिनसे हमारा संबंध है। जो मद 2502 के खंड (बी) के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में, यह बात उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार की गई थी।

एक बार जब हम उन सिद्धांतों और योजना को समझ लेते हैं जिनके अनुसार ड्रॉबैक की दरें निर्धारित की जानी हैं और निर्धारित की जाती हैं जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलकर्ताओं की दलील है कि निर्धारित शुल्क वापसी की राशि देय उत्पाद शुल्क से अधिक कुछ नहीं है प्लायस्टर फाइबर के साथ मिश्रित फाइबर का निर्माण, सामग्री और यह कि अधिसूचना में आयातित डीएमटी पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क की अनदेखी करके गलती की गई है, पूरी तरह से अस्थिर है। हम ऐसा दो कारणों से कहते हैं। सबसे पहले, निर्धारित दरें सीमा शुल्क अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के तहत देनदारियों को ध्यान में रखते हुए तय की गई ड्रॉबैक की एक समग्र दर का गठन करती हैं। सैद्धांतिक रूप से, इस प्रकार निर्धारित राशि को उसके दो घटकों में विभाजित करना और यह कहना सही नहीं होगा, केवल इसलिए कि निर्धारित राशि कर्तव्यों में से एक के बराबर है, कि दूसरे को ध्यान में नहीं रखा गया है। सिद्धांत रूप में, निर्धारित कमी में कर्तव्यों के दोनों सेटों को आंशिक रूप से ही ध्यान में रखा जा सकता था। इसे केवल सीमा शुल्क दोष या केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोष नहीं कहा जा सकता। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि आइटम 2502 के तहत निर्धारित शुल्क वापसी की विभिन्न दरें उसमें उल्लिखित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण पर देय उत्पाद शुल्क की दर के बराबर हैं, दी गई छूट की प्रकृति दोनों अधिनियमों के तहत राहत में से एक है। यह महत्वहीन है कि क्या राहत की यह मात्रा निर्धारिती को

एक या दूसरे या दोनों लेवी के संबंध में लाभ पहुंचाती है जिसका उसे भुगतान करना है। इसलिए भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर दी गई छूट को पहचानने और सहसंबंधित करने का प्रयास सैद्धांतिक रूप से सही प्रतीत नहीं होता है।

लेकिन, इस आधार के अलावा, हमारा मानना है कि भारत संघ के विद्वान वकील द्वारा कही गई और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई बात में दम है। कोर्ट ने कहा कि उस समय जब ये ड्रॉबैक दरें तय की गई थीं, तब भारत सरकार ने आयात शुल्क के साथ-साथ दोनों को भी ध्यान में रखा था उत्पाद शुल्क जो उन वस्तुओं के निर्माण पर देय होगा जिनके निर्यात को प्रोत्साहित करने का इरादा था। व्यापार की स्थिति की जांच करने पर पता चला कि डी.एम.टी. उस समय भारत में आसानी से उपलब्ध था और इसलिए, आयातित सामग्री पर सीमा शुल्क की कमी के संबंध में कोई राहत देना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि निर्धारित देश में ही उपलब्ध कच्चे माल को अनावश्यक रूप से आयात करने का प्रयास करेंगे। दरअसल, यही वह पहलू है जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी जोर दिया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और यह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारत सरकार ने अगस्त, 1976 में, डी.एम.टी. के आयात के लिए सीमा शुल्क के संबंध में छूट देने का निर्णय लिया था।

उनका कहना है कि यदि डी.एम.टी. यदि यह उस समय स्वदेशी रूप से आसानी से उपलब्ध होता, तो धारा 25 के तहत छूट देने का प्रश्न सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए, उनका कहना है कि, वापसी की दर तय करने में केंद्र सरकार इस आधार पर आगे बढ़ी थी कि डीएमटी पर कोई आयात शुल्क देय नहीं होगा और यह अकेले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में राहत देने के लिए पर्याप्त होगा। हम पाते हैं कि इस पहलू पर, स्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत की है। हमने करदाता के प्रतिनिधित्व पर भारत सरकार का जवाब पहले ही निकाल लिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि डीएमटी स्वदेशी रूप से उपलब्ध है और इसलिए, पॉलिएस्टर यार्न के निर्माण में कोई शुल्क नहीं लिया गया है। यह तथ्यात्मक बयान है और पहले उल्लिखित पत्राचार के अलावा इसका खंडन करने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है। यदि कोई पत्राचार को ध्यान से देखता है, तो वह पाएगा कि यह करदाता के मामले का समर्थन नहीं करता है। एक बात तो यह है कि एसोसिएशन द्वारा मार्च 1976 में प्रस्तुत जापन स्वयं इस आधार पर आगे बढ़ता है कि डीएमटी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। लेकिन घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह, स्पष्ट रूप से, उस चीज का संदर्भ है जो वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा अपना माल आयात करने और निर्माण शुरू करने के बाद हुआ था। दरअसल, उनका दावा है कि वे इस क्षेत्र में अग्रणी थे। निर्धारित के

अनुसरण में डीएमटी के आयात प्राप्त करने और निर्मित वस्तुओं, अन्य पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का निर्यात करने का प्रयास किया जाता है निर्माताओं ने ऐसे आयात और निर्यात की संभावनाएं तलाशने का भी प्रस्ताव रखा और पत्र जो कहता है वही प्रतीत होगा यदि व्यवसाय का इतना विस्तार हुआ तो डीएमटी और ग्लाइकोल की स्वदेशी आपूर्ति घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। जब दरें तय करने की अधिसूचना जारी हुई, तब तक डीएमटी पर आयात शुल्क हटा दिया गया था और, इसलिए, सीमा शुल्क में कमी देने का कोई उद्देश्य नहीं था। इन परिस्थितियों में, वापसी की दर तय करने में सीमा शुल्क को ध्यान में नहीं रखा गया। सरकार का पत्र दिनांक 09.09.76 केवल करदाता की प्रार्थना का उत्तर है कि उसकी समस्या का समाधान डीएमटी को सीमा शुल्क से छूट देकर किया जा सकता है और यह केवल छूट की अधिसूचना के बाद की स्थिति को संदर्भित करता है। यह अतीत के संबंध में निर्धारिती के अभ्यावेदन का उत्तर नहीं है जो कि बहुत बाद में 1977 में दायर किया गया था। इसलिए, मामले में पत्राचार से निर्धारिती को कोई मदद नहीं मिली। यह भी बताया जा सकता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारितियों ने डीएमटी का आयात किया है, इसलिए नहीं कि यह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था लेकिन केवल इसलिए कि वह इसे आईसीआई से निःशुल्क प्राप्त करने में सक्षम थी, जो एक ऐसा लाभ था जिसका लाभ अन्य निर्माता, यदि कोई हो, नहीं उठा सकते थे। इसलिए,

हमारी राय है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही था कि प्रश्न में माल के संबंध में वापसी की दर डीएमटी के संबंध में देय सीमा शुल्क के पहलू पर विचार करने के बाद तय की गई थी और यह एक सचेत निर्णय लिया गया था। इस संबंध में कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि डीएमटी देश में ही उपलब्ध थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां निर्धारण नियम 3 की शर्तों के विपरीत है और उसके मामले में दर के निर्धारण के लिए निर्धारित के आवेदन को नियम 6 के तहत एक आवेदन के रूप में लिया जाना चाहिए। नियम 6 इस कारण से भी लागू नहीं है कि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से पहले नियम 6 के तहत आवेदन किया जाना चाहिए जो कि यहां मामला नहीं लगता है। इसलिए, नियम 6 पर करदाता की निर्भरता विफल हो जाती है।

यह सच है कि नियम 3 में दर्शाए गए औसत आधार पर ड्राबैंक की दरों का निर्धारण व्यक्तिगत मामलों में कठिनाई पैदा कर सकता है। इस आकस्मिकता का प्रावधान नियम 7 में किया गया है। करदाता के आवेदन को इस नियम के तहत सही माना गया और वे राहत तभी मांग सकते थे जब उनका मामला इसकी शर्तों के अंतर्गत आता हो। यह नियम, दुर्भाग्य से, हर उस मामले में राहत प्रदान नहीं करता है जहां एक व्यक्तिगत निर्माता को अपने माल की श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा से अधिक सीमा तक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। राहत

केवल उन मामलों तक ही सीमित है जब अंतर का मार्जिन पर्याप्त है और नियम 7 में निर्दिष्ट सीमा तक है। उच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा की है और आवश्यक आंकड़े देकर प्रदर्शित किया है। कैसे निर्धारिती का मामला नियम की शर्तों को पूरा नहीं करता है और वास्तव में, इस निष्कर्ष को अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, ड्रॉबैक नियमों की धारा 7 के तहत अपीलकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार करने में सरकार सही थी। उपर्युक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि करदाता के आवेदन को खारिज करने का केंद्र सरकार का आदेश सही था और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील हमारे ध्यान में प्रकाशन निदेशालय द्वारा प्रकाशित एक मैनुअल लाते हैं। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नियमों के दायरे के साथ-साथ सरकार द्वारा क्रमशः 09.06.1978 और 01.02.1982 को जारी की गई दो अधिसूचनाओं की व्याख्या करता है और प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामला इन अधिसूचनाओं की शर्तों के अंतर्गत आता है। हम यह बताने के लिए बाध्य हैं कि ये हमारे सामने विवाद की अवधि के बाद जारी की गई अधिसूचनाएँ हैं: यह वह सामग्री भी है जिसे अधिकारियों या उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था। इसलिए, हम इस अंतिम चरण में निर्धारिती को उन पर भरोसा करने की अनुमति देने में खुद को असमर्थ पाते हैं। हालाँकि, उपरोक्त नियमों में परिस्थितियों और उसके बाद की नीति को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि यह एक उपयुक्त

मामला है जिसमें केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या न्यायसंगत आधार पर निर्धारिती को उसके द्वारा भुगतान किए गए डीएमटी पर सीमा शुल्क के संबंध में राहत दी जा सकती है। इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारिती ने डीएमटी को मुफ्त में आयात करके देश के लिए विदेशी मुद्रा बचाई। संपूर्ण निर्मित उत्पाद का निर्यात भी किया गया है और विदेशी मुद्रा भी अर्जित की गई है। अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर मिश्रित फाइबर के निर्यात के लिए अन्य निर्माताओं को भी प्रोत्साहन दिया। यदि अपीलकर्ताओं ने कुछ महीने बाद डीएमटी का आयात किया होता, तो वे सीमा शुल्क से छूट के हकदार होते और वर्तमान बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने सीमा शुल्क बांड के तहत डीएमटी को पॉलिएस्टर फाइबर में परिवर्तित करने के लिए सरकार की अनुमति भी प्राप्त की, लेकिन इसे उनके नियंत्रण से परे कारणों से लागू नहीं किया जा सका। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित और निष्पक्ष प्रतीत होगा कि करदाताओं को उस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसका अन्य सभी व्यक्तियों ने लाभ उठाया है। इसलिए, हम सोचते हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें सरकार को विचार करना चाहिए, यदि निर्धारिती आज से दो महीने के भीतर आवेदन करता है, क्या निर्धारिती को अपेक्षित राहत दी जा सकती है, भले ही केवल न्यायसंगत आधार पर, और ऐसे आवेदनों पर उचित आदेश पारित करें।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, ये अपीलें खारिज की जाती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

वाई लाल

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नेहा मौर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।